Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-5(A)| May-2026

Original Article

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति पर प्रभाव– झारखंड के दुमका जिले के विशेष संदर्भ में

Bablu Murmu
Assistant Professor (Nbap), Department of Economics Degree College, Shikaripara Skmu Dumka, Jharkhand
Email: Murmubablu.Iact@Gmail.Com

Manuscript ID:
JRD -2026-180526
ISSN: 2230-9578
Volume 18
Issue 5(A)
Pp.109-111
May- 2026
Submitted: 15 Apr. 2026
Revised: 25 Apr. 2026
Accepted: 10 May. 2026
Published: 31 May 2026

सारांश

भारत सरकार ने मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) का शुभारंभ किया, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क LPG गैस कनेक्शन प्रदान करना था। झारखंड का दुमका जिला, जो संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय है, आदिवासी एवं पिछड़ी जनसंख्या की अधिकता के कारण इस योजना के लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन क्षेत्र है। प्रस्तुत शोधपत्र में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों के आधार पर दुमका जिले में उज्ज्वला योजना के क्रियान्वयन, लाभार्थियों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य पर प्रभाव तथा योजना के सामने आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि यद्यपि योजना ने महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं, तथापि रिफिल की ऊँची कीमत, आर्थिक असमर्थता एवं जागरूकता की कमी जैसी समस्याएँ अभी भी बाधा बनी हुई हैं।

मुख्य शब्द– *उज्ज्वला योजना, ग्रामीण महिला, LPG, दुमका, सामाजिक–आर्थिक विकास, महिला सशक्तिकरण, झारखंड*

प्रस्तावना

भारत एक विकासशील देश है जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी करोड़ों परिवार पारम्परिक ईंधन जैसे लकड़ी, उपले, कोयला आदि पर निर्भर हैं। इन ईंधनों के उपयोग से उत्पन्न धुएँ से महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, भारत में प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख लोग घरेलू वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के कारण मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जिनमें महिलाओं एवं बच्चों की संख्या सर्वाधिक है। इसी पृष्ठभूमि में भारत सरकार ने 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) का शुभारंभ किया। इस योजना का लक्ष्य था कि वर्ष 2020 तक देश के 8 करोड़ BPL परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क LPG गैस कनेक्शन प्रदान किया जाए। बाद में उज्ज्वला 2.0 के अंतर्गत इसे और विस्तृत किया गया। झारखंड राज्य का दुमका जिला संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय है। यह जिला भौगोलिक दृष्टि से पहाड़ी व वनाच्छादित है तथा यहाँ की अधिकांश जनसंख्या आदिवासी एवं पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित है। 2011 की जनगणना के अनुसार दुमका जिले की कुल जनसंख्या लगभग 13.21 लाख है, जिसमें अनुसूचित जनजाति की हिस्सेदारी 43.5 प्रतिशत है। यहाँ साक्षरता दर 62.3 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता दर मात्र 51.9 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। ऐसे क्षेत्र में उज्ज्वला योजना का अध्ययन विशेष महत्व रखता है।

साहित्य समीक्षा

उज्ज्वला योजना पर अनेक अध्ययन किए गए हैं। प्रमुख शोधकर्ताओं के निष्कर्ष निम्नलिखित हैं–

सिंह एवं मिश्रा (2018) ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए अपने अध्ययन में पाया कि उज्ज्वला योजना से महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, परंतु LPG रिफिल की ऊँची कीमत के कारण अनेक लाभार्थी पुनः ठोस ईंधन की ओर लौट रहे हैं। शर्मा (2019) के अनुसार, इस योजना ने महिलाओं के समय की बचत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ईंधन संग्रह में लगने वाला समय कम होने से महिलाएँ आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियों में अधिक भाग ले पा रही हैं। कुमार एवं पांडेय (2020) ने झारखंड में अपने अध्ययन में पाया कि आदिवासी क्षेत्रों में योजना के क्रियान्वयन में अनेक समस्याएँ हैं, जैसे – दस्तावेजीकरण की जटिलता, वितरक की अनुपलब्धता, एवं डिजिटल साक्षरता की कमी। PAHAL (2021) की रिपोर्ट के अनुसार, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जारी कनेक्शनों में से लगभग 30–40% परिवार नियमित रूप से LPG का उपयोग नहीं कर पाते, जिसका मुख्य कारण आर्थिक असमर्थता है।

प्रस्तुत शोध इन सभी अध्ययनों से भिन्न है क्योंकि यह विशेष रूप से दुमका जिले की आदिवासी बहुल ग्रामीण महिलाओं पर केन्द्रित है।

शोध उद्देश्य

प्रस्तुत शोध के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

1. दुमका जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के क्रियान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन करना।
2. ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति पर योजना के प्रभाव का विश्लेषण करना।
3. लाभार्थी महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर उज्ज्वला योजना के प्रभाव का अध्ययन करना।
4. योजना के क्रियान्वयन में आने वाली प्रमुख चुनौतियों की पहचान करना।
5. योजना को अधिक प्रभावी बनाने हेतु नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)
This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public License, which allows others to remix, tweak, and build upon the work noncommercially, as long as appropriate credit is given and the new creations ae licensed under the idential terms.

Address for correspondence:
Bablu Murmu Assistant Professor (Nbap), Department of Economics Degree College, Shikaripara Skmu Dumka, Jharkhand

How to cite this article:
Murmu, B. (2026). प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर प्रभाव- झारखंड के दुमका जिले के विशेष संदर्भ में. Journal of research & development, 18(5(A)), 109–111. https://doi.org/10.5281/zenodo.20955175

Quick Response Code:
Website: https://jrdrvb.org/
DOI: 10.5281/zenodo.20955175
OPEN ACCESS

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-5(A)| May-2026

शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध में मिश्रित शोध पद्धति (Mixed Research Method) का उपयोग किया गया है। शोध में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों का उपयोग किया गया है।

(i) अध्ययन क्षेत्र

दुमका जिले के 5 प्रखंडों– दुमका, जरमुंडी, काठीकुंड, मसलिया एवं रामगढ़– से उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन (Purposive Sampling) विधि द्वारा 250 लाभार्थी महिलाओं का चयन किया गया।

(ii) प्राथमिक आँकड़े

प्राथमिक आँकड़ों के संग्रह के लिए संरचित प्रश्नावली (Structured Questionnaire), साक्षात्कार एवं फोकस समूह चर्चा (FGD) का उपयोग किया गया। प्रश्नावली को स्थानीय भाषा (हिंदी एवं संथाली) में अनुवादित किया गया।

(iii) द्वितीयक आँकड़े

द्वितीयक आँकड़े– जिला प्रशासन, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG), NSSO सर्वेक्षण, राज्य सरकार की वार्षिक रिपोर्ट एवं जनगणना 2011 से प्राप्त किए गए।

(iv) विश्लेषण विधि

आँकड़ों के विश्लेषण में प्रतिशत विश्लेषण, बारंबारता वितरण, क्रॉस–टेबुलेशन एवं सरल रेखा–चित्रों का उपयोग किया गया है।

आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या

(i) लाभार्थियों की सामाजिक पृष्ठभूमि

अध्ययन के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल 250 महिलाओं में से 64% अनुसूचित जनजाति (ST), 18%अनुसूचित जाति (SC) एवं 18% अन्य पिछड़े वर्ग (OBC) से थीं। लगभग 71% महिलाएँ कृषि एवं मजदूरी पर निर्भर थीं। 62% परिवारों की मासिक आय 5,000 रुपये से कम थी।

तालिका 1: लाभार्थियों की सामाजिक श्रेणी (n=250)

श्रेणी	संख्या	प्रतिशत (%)
अनुसूचित जनजाति (ST)	160	64%
अनुसूचित जाति (SC)	45	18%
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	45	18%
कुल	250	100%

(ii) कनेक्शन प्राप्ति एवं उपयोग की स्थिति

सर्वेक्षण में पाया गया कि 250 में से 238 (95.2%) महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत LPG कनेक्शन प्राप्त हो चुका है। परंतु चिन्ताजनक तथ्य यह है कि केवल 54% महिलाएँ नियमित रूप से LPG का उपयोग करती हैं, जबकि 28% केवल कभी–कभी उपयोग करती हैं एवं 18% पुनः लकड़ी–उपले की ओर लौट चुकी हैं।

तालिका 2: LPG उपयोग की स्थिति (द=238)

उपयोग की स्थिति	संख्या	प्रतिशत (%)
नियमित उपयोग	129	54%
कभी–कभी उपयोग	67	28%
स्च्ळ छोड़ दिया (पारंपरिक ईंधन)	42	18%
कुल	238	100%

(iii) स्वास्थ्य पर प्रभाव

अध्ययन के दौरान पाया गया कि LPG का नियमित उपयोग करने वाली 129 महिलाओं में से 78% ने श्वसन संबंधी बीमारियों में कमी महसूस की। आँखों में जलन एवं सिरदर्द की शिकायतें भी 65% कम हुईं। बच्चों में खाँसी एवं श्वास संबंधी समस्याओं में 60% की कमी देखी गई।

जिला अस्पताल दुमका के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2016–17 की तुलना में 2022–23 में श्वसन रोगों से ग्रसित मरीजों की संख्या में 22% की कमी आई है, जिसे आंशिक रूप से LPG के बढ़ते उपयोग से सम्बन्धित किया जा सकता है।

(iv) सामाजिक–आर्थिक प्रभाव

उज्ज्वला योजना का महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति पर भी उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा है। ईंधन एकत्रित करने में लगने वाले औसत समय में 3 से 4 घंटे प्रतिदिन की बचत हुई है। इस बचे हुए समय का उपयोग महिलाएँ स्वयंसहायता समूहों, लघु उद्योग एवं बच्चों की देखभाल में कर रही हैं।

सर्वेक्षण में शामिल 68% महिलाओं ने बताया कि खाना पकाने का समय कम होने से बच्चों की स्कूली शिक्षा पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। लगभग 42% महिलाओं ने कहा कि उनके परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है।

(v)योजना के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

दुमका जिले में योजना के क्रियान्वयन में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएँ सामने आईं–

1. LPG रिफिल की ऊँची कीमत– 82% लाभार्थियों ने रिफिल सिलेंडर की ऊँची कीमत को सबसे बड़ी बाधा बताया।
2. वितरक की दूरी– दुमका के दूरदराज क्षेत्रों में LPG वितरक 20–30 किलोमीटर दूर हैं।
3. दस्तावेजीकरण की समस्या– आदिवासी क्षेत्रों में अनेक पात्र परिवारों के पास आधार कार्ड एवं बैंक खाता नहीं था।
4. डिजिटल साक्षरता की कमी– ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से अधिकांश महिलाएँ अपरिचित थीं।
5. सब्सिडी में कमी– DBT के माध्यम से मिलने वाली सब्सिडी की राशि पर्याप्त नहीं पाई गई।

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-5(A)| May-2026

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना दुमका जिले में एक महत्वाकांक्षी एवं आवश्यक कल्याणकारी योजना के रूप में उभरी है। योजना ने महिलाओं के जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं– विशेष रूप से स्वास्थ्य सुधार, समय की बचत एवं सामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में।

तथापि, कनेक्शन प्राप्ति के बाद LPG के नियमित उपयोग की कम दर (54%) यह दर्शाती है कि केवल कनेक्शन देना पर्याप्त नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को LPG का निरंतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक सहायता की आवश्यकता है।

दुमका जैसे आदिवासी बहुल जिले में योजना को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

नीतिगत सुझाव

1. LPG रिफिल पर विशेष सब्सिडी– BPL एवं आदिवासी परिवारों को रिफिल पर अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाए।
2. मोबाइल वितरण सेवा– दूरदराज क्षेत्रों में LPG सिलेंडर की घर–घर आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
3. जागरूकता अभियान– ग्राम पंचायत स्तर पर महिला स्वयंसहायता समूहों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएँ।
4. दस्तावेजीकरण सहायता– वंचित परिवारों के आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं बैंक खाता खुलवाने में सरकारी सहायता दी जाए।
5. आजीविका से जोड़ना– उज्ज्वला लाभार्थियों को MGNREGA, SHG एवं अन्य योजनाओं से जोड़कर उनकी आय में वृद्धि की जाए।
6. निगरानी तंत्र– योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर नियमित समीक्षा बैठकें एवं डेटा संग्रह सुनिश्चित किया जाए।

संदर्भ सूची

1. सिंह, आर. एवं मिश्रा, पी. (2018). उज्ज्वला योजना और ग्रामीण महिला सशक्तिकरण. भारतीय अर्थशास्त्र पत्रिका, 45(2), 112–128.
2. शर्मा, एस. के. (2019). LPG योजनाओं का महिलाओं के समय उपयोग पर प्रभाव. समाज विज्ञान शोध, 33(4), 89–104.
3. कुमार, ए. एवं पांडेय, एम. (2020). झारखंड में उज्ज्वला योजना का मूल्यांकन. झारखंड जर्नल ऑफ सोशल साइंस, 12(1), 45–67.
4. https://mopng.gov.in/en/documents/annual-reports, Ministry of Petroleum and Natural Gas (2022)- PMUY Annual Report 2021–22.Government of India, New Delhi-
5. https://censusindia.gov.in/nada/index.php/catalog/566, https://dumka.nic.in/demography/, Census of India (2011)- District Census Handbook — Dumka- Office of the Registrar General, New Delhi-
6. https://www.data.gov.in/catalog/household-consumer-expenditure-national-sample-survey, NSSO (2019)- Household Consumer Expenditure Survey, 76th Round- Ministry of Statistics, Government of India-
7. https://www.who.int/data/gho/data/themes/air-pollution/who-air-quality-database/2018, WHO (2018)- Household Air Pollution and Health: Global Update- World Health Organization, Geneva-
8. https://pmujjwalayojana.com/, PAHAL (2021)- Impact Assessment of PM Ujjwala Yojana- PAHAL Research Centre, New Delhi-
9. https://dumka.nic.in, जिला सांख्यिकी कार्यालय, दुमका (2023). जिला वार्षिक सांख्यिकीय रिपोर्ट 2022–23. झारखंड सरकार.
10. https://ppac.gov.in/consumption/state-wise-pmuy-data, Petroleum Planning and Analysis Cell (2023)- LPG Profile — Jharkhand- MoPNG, Government of India-